अमेरिकी विदेश नीति के निर्धारक तत्व

द्वारा:- डॉ.कुमार राकेश रंजन
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान विभाग
एल.एन.डी.कॉलेज, मोतिहारी

किसी भी देश की विदेश नीति के कतिपय निर्धारक तत्व होते हैं जिनके आधार पर संबंधित देश की विदेश नीति की दिशा एवं दशा तय की जाती है। प्रारंभिक काल से ही अमेरिका विश्व में अपनी एक ध्रुवीयता कायम रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश नीति के निम्नलिखित निर्धारक तत्व हैं:

I.भौगोलिक स्थिति
II.प्राकृतिक संसाधन
III.सुरक्षात्मक शक्ति
IV.मानव संसाधन
V.गृह नीति एवं दवाब गुट
VI.संवैधानिक बाध्यता
VII.दलीय सहयोग

I. भौगोलिक स्थिति: एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था कि "यह देश ऐसा भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर निर्बल पड़ोसी बसते हैं और पूरब एवं पश्चिम में मछलियां ।" भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका काफी भाग्यशाली है उसके पास प्राकृतिक साधनों का विपुल भण्डार है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका की विश्व में वाणिज्य और व्यापार में आशातीत वृद्धि हुई है। अमेरिका की आधारभूत नीतियां उसकी भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी गोलार्द्ध की सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हैं। जलवायु, पहाड़ों और नदियों ने राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा नहीं पहुंचायी है।

II. प्राकृतिक संसाधन: यदि आर्थिक आत्म- निर्भरता शक्ति का एक तत्व है तो अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता हैं। खाद्योत्पादन जो कि कभी गृह समस्या थी आज अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है।

III. सुरक्षात्मक शक्ति: निर्बलता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। उन नीतियों की अपेक्षा जो उच्च आदर्शों और ऊंची आशाओं पर आधारित होती हैं शक्ति नीतियां अधिक सफल होती हैं। अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके।

IV. मानव संसाधन: औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर-पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण हाथ है।

V. गृह नीति एवं दबाव गुट: गृह नीति और दबाव गुटों का अमेरिका की विदेश नीति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना असम्भव हो जाता है। अमेरिका की फिलिस्तीन सम्बन्धी नीति अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी। धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं तथा दूसरे सामाजिक संगठन भी विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करते रहते हैं।

VI. संवैधानिक बाध्यता: जनतन्त्रात्मक और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के सचालन में केन्द्रीय सरकार के हाथों को जकड़ रखा है। राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसके 'युद्ध' और 'सन्धि' आदि के निर्णयों पर सीनेट का अंकुश लगा रखा है ।

VII. **दलीय सहयोग:** अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलीय सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर रहता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती है, जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिसका कि कांग्रेस में बहुमत होता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की विदेश नीति के साथ-साथ व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि (CTBT) के भविष्य को एक बड़ा झटका उस समय लगा जब रिपब्लिकनों के वर्चस्व वाली अमरीकी सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया। 100 सदस्यों वाली

सीनेट में 13 अक्टूबर, 1999 को इसकी पुष्टि के लिए हुए मतदान में सीनेट ने इसे 48 के मुकाबले 51 मतों से अस्वीकार कर दिया।
सन्धि के अनुमोदन के लिए दो-तिहाई मतों (67 मत) का इसके पक्ष में होना आवश्यक था। राष्ट्रपति क्लिंटन ने सन्धि के अनुमोदन के लिए भारी प्रयास करते हुए इसके लिए सीनेटरों से अपील की थी। राष्ट्रपति पद के अपने दूसरे कार्यकाल में इस सन्धि को ही उन्होंने अपनी विदेश नीति का प्रमुख मुद्दा बनाया था।
उपरोक्त निर्धारकों के आधार पर अमेरिका की विदेश नीति निर्धारित होती रही है वह विश्व में अपनी एक ध्रुवीयता कायम रखने के लिए यथासंभव सदा यथोचित प्रयास करता रहता है।